

संपादकीय
विविटम कार्ड
का सहारा

उचित यह होता कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अधिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते समय उड़ाए गए सवालों के तथ्यप्रकर जवाब देश के सामने रखते। लैंकिन उड़ाने अडानी का नाम तक नहीं लिया।

लोकसभा में राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और सरकार से अडानी प्रक्रिया में खास प्रश्न पूछे थे। उचित यह होता कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अधिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते समय उन सवालों के तथ्यप्रकर जवाब देश के सामने रखते। लैंकिन उड़ाने अडानी का नाम तक नहीं लिया।

लैंकिन उड़ाने गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और सरकार से अडानी प्रक्रिया में खास प्रश्न पूछे थे। उचित यह होता कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अधिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते समय उन सवालों के तथ्यप्रकर जवाब देश के सामने रखते। लैंकिन उड़ाने अडानी का नाम तक नहीं लिया।

लैंकिन उड़ाने अडानी का नाम तक नहीं लिया।

लैंकिन उड़ाने अडानी का नाम तक नहीं लिया। इसके विपरीत उड़ाने के लिए नहीं बोला गया। इसके साथ ही उड़ाने का कोर्टोंस के पतन पर लंबा वक़्त दिया और विपक्ष के 'निराशाओं' का जिक्र किया। और दावा किया कि उड़ाने का आम अखबारों सुनियों वा टीवी चर्चाओं से नहीं, बल्कि देश के लिए समर्पण से होता है। जानकारी कल्पना योजनाओं के उड़ाने खुद से जोड़ा और कहा कि उनसे लालान्तर लाग विपक्ष के आरोपों पर भरोसा नहीं करें।

सदन में प्रधानमंत्री बोलते, इसके पहले ही सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गुहल गांधी के भाषण के कृत 18 हिस्से कायवाली से बाहर दिया। इनमें वो हिस्से भी शामिल है, जिनमें गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया था।

राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की एक पुरानी तस्वीर सदन में दिखाई थी, जिसे भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। उधर राजसभा में एक और सिद्धांत विपक्ष के विपरीत किया गया। इसमें कहा गया कि सदन में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हो सकती, बल्कि प्रधानमंत्री एक सल्ला है। अब देश के विवेकशील लोगों के सामने यह विचारपूर्ण प्रश्न है कि क्या जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उसे किस ढंग का लोकतंत्र कहा जाए? लोकतंत्र का आम सिद्धांत जोहाने होते हैं। सवाल पूछे गए हैं, तो जवाब देना सरकार का काम है। इसी तरह प्रधानमंत्री सबसे बाहर है, यह धराघास सिरे से असंविचित है। बल्कि ब्रिटिश व्यवस्था में (जिसे हमने अपनाया है) प्रधानमंत्री को कैबिनेट में समान दर्जे वाले परवारियों के बीच प्रभाव होने का मान्यता ही रही है। इसी अंतर पर कैबिनेट के समानिक वापर का सिद्धांत प्रचलन में रहा है। लैंकिन विवरान सरकार के तहत तमाम नए सिद्धांत और परिपालियां गढ़ी जा रही हैं। इस परिवर्तन पर हार पहुंच गया। यह धराघास सिरे से असंविचित है।

राहुल गांधी ने अडानी को एक अंतर पर कैबिनेट के समानिक वापर का सिद्धांत प्रचलन में रहा है।

उचित यह होता कि उड़ाने नहीं जोड़ा जाए।

उचित

